

ont>

12.54 hrs

Title: Regarding nomination of associated members in the Delimitation Commission.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिस के प्रति दोनों पक्षों के लोग एक हैं और वह डिलिमिटेशन कमीशन का मामला है। डिलिमिटेशन एक्ट 2002, के मुताबिक डिलिमिटेशन कमेटी का गठन हो गया। उसमें आपने एज ए स्पीकर प्रत्येक राज्य से अधिक से अधिक पांच मैम्बर्स को नियुक्त किया है। उसमें 10 एसोसिएटिड मैम्बर्स होते हैं जिन में से पांच लोक सभा और पांच असेम्बली के होते हैं। इनको नॉमिनेट किया जा चुका है बहुत दिन हो गए हैं लेकिन आज तक उस डिलिमिटेशन कमेटी का ऑफिस कहां है, वह कहां काम कर रहा है, क्या हो रहा है, किसी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को पता नहीं है। डिलिमिटेशन एक्ट के मुताबिक यह लिखा है *The Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of each State.*

सभी मैम्बर्स का काम एसोसिएट करना और उनको असिस्ट करना है लेकिन किसी मैम्बर को इसका पता नहीं है। इसलिए यह आपका मामला है, हम लोगों का मामला नहीं है। या तो सब को हटा दीजिए। बनी बनायी चीज आए और उसके बाद हम सब को मोहर लगाने के लिए कहा जाए, मैं समझता हूँ कि यह प्रिविलेज का मामला है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एसोसिएटिड मैम्बर्स की एक्ट में कहीं डेफिनेशन नहीं है लेकिन यह ड्यूटी मानी जाती है कि वोटिंग राइट्स के अलावा मैम्बर्स के सब अधिकार उनके पास मौजूद हैं।

लेकिन मैं दोनों पक्षों की तरफ से कहता हूँ कि किसी भी मैम्बर को इस बात की जानकारी नहीं है। इसलिये मैं आपसे रूलिंग चाहता हूँ कि आप एसोसिएटिड मैम्बर्स को प्रोटैक्ट करने का काम कीजिये।

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, we also associate ourselves with this issue. ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: I have only one more notice which I have received from Shri Priya Ranjan Dasmunsi. If other Members also want to speak on this, I am doubtful whether your subject can be taken up. मैं सब को अनुमति नहीं दे सकता।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में यह इनफॉर्मेशन लीक हो रही है।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : The very Act of Delimitation which was passed by this House did indicate firstly that the year 1991 should be the basis. Section 5 of the Act that we have passed provides for the role of the Associate Members. I had the privilege to serve the Delimitation Commission in 1971 when I was in this House. At that time the procedure was that the State Electoral Office shall prepare a draft document consulting the Associate Members and the Members and that draft should come to the main Commission. The commission will go on hearing that draft involving the sitting MPs of that particular House to know their observations.

Unfortunately now the basic departure is that the State Electoral Office has not been asked to prepare any draft; Members also have not been asked to give any proposals; a *suo motu* draft has been prepared from the Central Delimitation Council and suddenly the Members are called and told that this is the draft and this is the summary. In 99 per cent of cases the fate of the Members and their constituencies are decided in a *suo motu* manner.

Secondly, no specific guideline has been formulated pertaining to the role of the Associate Members in the Delimitation Commission as to how they will proceed on the issue. Thirdly, - and this is most important - the Delimitation Act complements to only readjustment of the boundaries of Assembly and Lok Sabha constituencies whereas in this case the entire reorganisation of the constituency is being done. Therefore, a lot of apprehension has been created. I desire that the hon. Law Minister should first consult the present Members who are in the capacity of Associate Members to know the details without wasting the time of the House and come back to the House with the comprehensive guidelines, and if necessary with necessary amendment to the main Act also.

I think that can solve the problem to a great extent. Otherwise, I am afraid, we are all under suspicion and doubt as to what is being done to our constituencies and nobody is taken into confidence.

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो दोनों माननीय सदस्यों ने बात कही है, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि दिल्ली के साथ भी यही हुआ है। इंटरैक्टिंग बात यह है कि ड्राफ्ट पहले आया कि डी-लीमिटेशन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है लेकिन अगली मीटिंग में आया कि तीन सदस्यों में से एक सदस्य की ओर से दिया जा रहा है जबकि मैम्बर्स को पता नहीं है। हम से कहते हैं कि इस बारे में बात करिये लेकिन अपनी बात मत करिये। इसके पहले भी कमीशन बने हैं, हम हाजिर हुये हैं लेकिन जिस तरह से यह कमीशन काम कर रहा है, उससे मुझे लगता है कि ₹ (व्यवधान) यहां बी.जे.पी. की बात नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस है। मैं कह रहा था कि मनोवृत्ति यह है कि जो हमने बना दिया, वह फाइनल होगा। क्या किसी मैम्बर की कोई वेल्यू नहीं है? मेरा कहना है कि इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष जी, एक छोटी सी बात यह कहना चाहता हूँ कि इस डी-लिमिटेशन कमीशन का आधार 1991 बनाया गया है जबकि यह 2001 होना चाहिये था। दिल्ली की आबादी 1991 में 94 लाख थी जो आज बढ़कर डेढ़ करोड़ हो गई है। इसलिये मेरा कहना है कि इस कमीशन का आधार 2001 होना चाहिये था। जो प्रक्रिया है, उसके अंदर पुनर्विचार करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कमीशन ने हम पर थोप दिया? सरकार इसे करेगी या नहीं?...*(व्यवधान)*

13.00 hrs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन से डीलिटिमिटेसन आयोग का गठन हुआ और कानून के तहत आपने हम लोगों का नाम उसमें चयन किया कि डीलिटिमिटेसन आयोग में हम लोग एसोसिएट रहेंगे। लेकिन डीलिटिमिटेसन कमीशन की कहीं कोई बैठक नहीं होती है और न कोई राय-मशविरा लिया जाता है। जिस बात के लिए इस कमीशन का गठन हुआ, वह काम नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार डीलिटिमिटेसन कमीशन को भंग करे या हम लोगों का नाम उसमें से हटा दिया जाए। जो सरकार को उचित लगे वह सरकार करे। हम लोगों से कुछ पूछा नहीं जाता है, कोई राय-मशविरा नहीं किया जाता है। उसका डी.डी. एडजस्टमेंट करना है, क्षेत्र को इधर-उधर करना है, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। यह कौन कर रहा है, इसके लिए सरकार कसूरवार है, वह ऐसी हेरा-फेरी से काम करवा रही है। सरकार या तो इसे भंग करे या हम लोगों का नाम इसमें से काट दे। हम लोग इसमें रहना नहीं चाहते हैं।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : इसमें आप पोलिटिक्स मत लाइये ठीक! (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : इसमें पोलिटिक्स मत लाइये कि यह बी.जे.पी. का है या कांग्रेस का है। जैसे भी हो इस पर विचार करें और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस बारे में तय करें।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, let the Law Minister take a meeting of the associated members and decide on the issue!...(Interruptions)

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डीलिटिमिटेसन एक्ट बनने के बाद वहां से इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हम इसी तरह से काम करेंगे। पेपर्स में रोज छपता है कि डीलिटिमिटेसन कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट्स आई हैं या तो जो पेपर्स की रिपोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो, यदि डीलिटिमिटेसन कमीशन ने ये रिपोर्ट्स मध्य प्रदेश में दी हैं। खुराना जी ने जो किया है, उसको हम सपोर्ट करते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इसे तय कर लिया जाना चाहिए।

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, I have a different matter to raise!...(Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I have also given a notice.....(Interruptions)

MR. SPEAKER: It seems there are many Members who are desirous of speaking on this issue. There are many Members and political parties who would like to express their views on this issue. The issue is concerning the Law Minister. I want to know whether the Government would like to make any observation on this issue.

On the issue of delimitation, it seems that the whole House is very sensitive. They want this issue to be considered and want to express their opinions. Some Members have already expressed themselves. Now, I cannot allow every Member to speak on this issue. Would the Government like to say something on this issue?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावनाओं से विधि मंत्री को अगवत करा दूंगी और चाहूंगी कि बेहतर होगा कि एक सर्वदलीय बैठक बुला लें, चूंकि सारा सदन इस पर एकमत है और सबकी बात सुनने के बाद वह आगे की कार्यवाई करेंगे! (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Kunwar Akhilesh Singh, I have disallowed your notice of adjournment motion. You are allowed to speak only on the issue that you have mentioned in your notice and nothing beyond that.

...(Interruptions)

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, I have a different matter to raise. You may please allow me to speak. Two weeks back, the Home Minister assured this House that he would make a statement on firing of adivasis in Kerala!...(Interruptions)

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, even today, a lot of people are missing.....(Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI(RAIGANJ) : Sir, the Home Minister assured the House that he would make a statement on the issue of adivasis..! (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have told you that I am disposing of those matters which are raised in the House in the form of Adjournment Motions.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please listen to me. All other notices have been disposed of except the notice of Kunwar Akhilesh Singh. I am going to give him two minutes to speak and thereafter, you can raise the issue of Madhya Pradesh which you are trying to raise for a long time. Thereafter, Shri Suresh Kurup, you may also speak. Please sit down now.

...(Interruptions)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, matters relating to States are raised everyday in this House.....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have not admitted his notice. But I have said that â€¦

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If so many Members want to speak simultaneously, I cannot give anybody a chance to speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, you can ask me as to what you exactly want. I am not able to understand.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down. Only one Member should speak. But others must sit down. Only one Member will be allowed to speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Member, you want to speak and the other Member also wants to speak. There is no discipline at all. Let me listen to him. I have permitted him. After him I will allow you.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please tell me what you want.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let me listen to the Member as to what he wants to say.

...(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): Sir, this is a State subject. ...(*Interruptions*)

SHRI N.N. KRISHNADAS : Sir, this is not a State subject. ...(*Interruptions*) Even today the *adivasis* are missing. â€¦
(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Krishnadas, are you not going to sit down?

...(*Interruptions*)

SHRI N.N. KRISHNADAS : No. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have not permitted you to raise the issue that you want to raise.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है - आप बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं खड़ा रहता हूँ तो भी आप सभी खड़े हो जाते हैं?

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are all elderly people. You are sent by lakhs of people to this House. You have no discipline.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please listen to me. What is this?

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have not permitted him. Why should you start shouting? This is not the way in which the House should be conducted. I am only telling him that on the issue that he have given notice, he can speak later.

...(*Interruptions*)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I have given a notice. ...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, मैं क्या करूँ आपके बारे में?

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have noticed that you have given a notice.

...(Interruptions)